keep seven Mandals in Telangana only and I also demand to consider alternative design for Polavaram.

Demand to make a concrete policy for reporting the crimes against women by newspapers and other media in the country

श्री बसावाराज पाटिल (कर्णाटक): माननीय उपसभापति महोदय, माननीय गृह मंत्री के माध्यम से मैं इस विशेष उल्लेख के द्वारा देश से जुड़े एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में भारत सरकार का ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं। महिलाओं पर अत्याचार, हत्याएं,दिनदहाड़े चोरी, विशेषकर नगरों में महिलाओं के गहने और पैसे लूटना आदि, साथ ही साथ वाहनों का अपघात, विशेषकर दुपहिया वाहनों पर घूमने वाले युवकों की मृत्यु, ऐसे समाचारों को छापते समय समाचार पत्र और अन्य मीडिया के माध्यमों के तौर-तरीकों से समाज की आंतरिक सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि मनोविज्ञानियों, अन्यान्य अपराध विभागों के विशेषज्ञों से चर्चा कर इन विषयों पर सरकार की नीति क्या हो, टीवी, मोबाइल, समाचार-पत्र और विज्ञापन के अन्य माध्यमों के तौर-तरीकों आदि, इन सब विषयों पर गंभीरता से विचार करके आवश्यकता पड़ने पर ऐसे विषयों में रुचि रखने वाले लोगों की एक विशेष समिति का गठन कर उपरोक्त वर्णित समस्याओं को रोकने के लिए तथा महिलाओं को सम्मानित जीवन जीने के लिए ठोस कदम उठाएं। साथ ही साथ विज्ञापनों और समाचारों के प्रकाशन और प्रसारण के बारे में भी कोई ठोस रीति और नीति बनाएं, ऐसा मैं सरकार से आग्रह करता हूं।

Demand for Central assistance to set up desalination plants for providing drinking water in Tamil Nadu

SHRI T. RATHINAVEL (Tamil Nadu) : Sir, Tamil Nadu is a water-deficit State. The State has very little surface water. Ground water level is fast receding due to various reasons including scanty monsoon. But for the timely steps taken by the Government of Tamil Nadu to make rainwater harvesting mandatory, ground water table would have been far worse. Under these circumstances, there is hardly any scope to increase the existing supply or create new sources through conventional methods. The projected demand of water requirement by 2017 to Chennai city alone is 1,584 million litres per day. However, the supply from present sources is only 831 MLD. Therefore, setting up of major desalination plants in the State to convert sea water into drinking water is the only option available with the Tamil Nadu Government.

At present, Tamil Nadu has only two 100 MLD capacity desalination plants. In order to meet the huge demand for water, Tamil Nadu has proposed four schemes. A 150 MLD SWRO Desalination plant at Nemmeli near Chennai at a cost of ₹ 1,371.86 crores, a 400 MLD SWRO Desalination plant at Perur near Chennai at a cost of ₹ 4070.67 crores and two desalination plants at Ramanathapuram and Tuticorin 100 MLD capacity at a cost of ₹ 1,500 crores each. Detailed Project Report is ready for the first two projects. For Ramanathapuram and Tuticorin projects, DPR will be ready by December, 2014.

[Shri T. Rathinavel]

Sir, the Tamil Nadu Government needs huge funds for implementing these schemes. In view of this situation, I request the Centre to bear, at least, 50 per cent of the cost of these proposed projects.

Demand to formulate a plan for development of Khambhat city in Gujarat as a port city

श्री लाल सिंह वडोदिया (गुजरात): महोदय, गुजरात राज्य में स्थित खम्भात शहर प्राचीन काल में बंदरगाह के रूप में विकसित था। उस समय इस बंदरगाह से विश्व के लगभग 84 देशों से व्यापार होता था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जहांगीर की मां हज करने मक्का गई थीं, तो इसी बंदरगाह का उपयोग किया गया था और उनकी मां की निगरानी के लिए खम्भात के नवाब साहब ने दो जहाज भेजे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय इस शहर की यातायात व्यवस्था बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ थी। इसी शहर में एक मही नदी बहती है जिसकी धारा में पर्वतों से मिट्टी आदि बहकर आने लगी, जिसकी सफाई न किए जाने के कारण धीरे-धीरे नदी का धरातल ऊंचा होता चला गया, फलस्वरूप वहां पर मैदान हो गया और बंदरगाह का काम बंद हो गया। इस बंदरगाह के चालू हो जाने से अभी जो मध्य गुजरात से सौराष्ट्र जाने वालों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है, वह तो कम हो ही जाएगी, साथ ही वहां के लोगों के लिए नए-नए रोजगार मिलने भी प्रारंभ हो जाएंगे। मेरे विचार से यदि वहां पर समुद्र और मही नदी के बीच बने मैदान में एक चैनल बना दिया जाए, तो खम्भात शहर को दोबारा बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा सकता है। अतः मेरा जहाजरानी मंत्री जी से विशेष रूप से अनुरोध है कि कृपया खम्भात शहर को पुनः बंदरगाह के रूप में विकसित करने के लिए योजना बनाने की कृपा करें ताकि मध्य गुजरात की जनता को इसका लाभ मिल सके।

Demand to take effective measures for strict compliance of rules under the Contract Labour Act

SHRI HUSAIN DALWAI (Maharashtra): There are an estimated 18 lakhs 44 thousand contract workers working in various Central Government Departments and public sector undertakings all over the country. Estimates of such workers working in similar organizations run by State Governments are not readily available. However, both the Central and State Governments are resorting to the practice of appointment of workers both male and female on contract basis on large scale. The Central Government has received complaints regarding non-compliance of various provisions of the law which includes wages and social security benefits.

The salary or wages, holidays, hours of work and other fringe benefits differ in both regular as well as those appointed on contract basis for similar kind of works. Any violation of rules framed under the Contract Labour Act is punishable.

However, in reality, the contract workers are being exploited today. They are not treated properly. Instances have come to our notice and also in the press where the workers engaged on contract basis are treated badly by their employers.